

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198]

दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2019/भाद्र 12, 1941

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 165

No. 198]

DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2019/BHADRA 12, 1941

[N.C.T.D. No. 165

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 सितम्बर, 2019

सं. 23/2018-राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(23)/ वित्त (राज-1)/2019-20/डीएस-IV/383.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 11 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सं0फा0 03(15) /वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/380 दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 41 के समक्ष, कॉलम (3) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करती है, यथा:-

“स्पष्टीकरण – इस छूट के उद्देश्य के लिए, ऐसे निकाय में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का सीधे तौर पर या ऐसे किसी निकाय के माध्यम से जो कि पूर्णतया केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के स्वामित्व में आता हो, 50% का स्वामित्व अवश्य होना चाहिए।”

2. यह अधिसूचना 20 सितम्बर, 2018 से प्रवर्तित होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

टिप्पण : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं.फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/380, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2018-राज्य कर (दर) दिनांक 02/09/2019, सं. फा. 03(5)/वित्त(राज.-1)/ 2019-20/डीएस-VI/371 दिनांक 02/09/2019 के द्वारा संशोधन किया गया है।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd September, 2019

No. 23/2018 – State Tax

No. F. 3 (23)/Fin (Rev-I)/2019-20/ DS-VI/383.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I) No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no.F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017, hereby inserts the following Explanation in the said notification, in the Table, against serial number 41, in column (3), namely:-

“Explanation.-For the purpose of this exemption, the Central Government, State Government or Union territory must have 50 percent ownership in the entity directly or through an entity which is wholly owned by the Central Government, State Government or Union territory.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of September, 2018.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

Note : The principal notification No.12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380 dated 30th June, 2017 and was last amended vide notification No. 14/2018-State Tax (Rate), dated 02.09.2019, vide No. F.3(5)/Fin. (Rev-I)/2019-20/DS-VI/371 dated 02.09.2019.